



जनसत्ता 2 अगस्त, 2014 : मोदी सरकार बनने के बाद यह पहला मौक है जब अमेरिका के किसी प्रमुख प्रतिनिधि ने दिल्ली का रुख किया। अमेरिकी वदेशमंत्री जॉन केरी ने दिल्ली पहुंचने से पहले ही सबका साथ सबका विकास के भाजपा के चुनावी नारे की तारीफ कर और उसे कूटनीतिक रंग देते हुए खुशनुमा माहौल बनाने की केशशि की। लेकिन उन्हें अहसास हो गया होगा कि यथार्थ इतना सरल नहीं है। यों उनसे हुई बातचीत में भारत की वदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने जोर देकर कहा कि सरकार बदलने से वदेश नीति नहीं बदल जाती; अमेरिका से जो रणनीतिक संबंध बना है वह जारी रहेगा। लेकिन यह भी साफ हो गया कि कई मामलों में दोनों पक्षों के बीच खटास भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले महीने होने वाली अमेरिका यात्रा के मद्देनजर स्वाभाविक ही केरी उस समय उभरने वाले मुद्दों का जायजा लेना चाहते रहे होंगे। लेकिन उनके दिल्ली दौरे का मकसद इतना ही नहीं था। उनके आने के पीछे खास में जेंडा यह भी था कि अमेरिका भारत के बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। यह अपने आप में कुछ गलत नहीं है, खासकर विशाल अर्थव्यवस्थाओं वाले सभी देश इसकी जुगत में लगे रहते हैं।

समस्या यह है कि कई मामलों में अमेरिका का रुख भारत के हितों से मेल नहीं खाता। केरी ने सुषमा स्वराज और फिर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के दौरान भी विश्व व्यापार संगठन के प्रस्तावित ट्रेड प्रोसेसिंग गरीमेंट यानी सुगम व्यापार समझौते को स्वीकार कर लेने का आग्रह किया, जिसे भारत नामंजूर कर चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह वृद्धि सबसे डी और न्यूनतम समर्थन मूल्य को बेहद सीमा तक देने की नीति पर टी.पी.के. मंजूर नहीं कर सकता। वडिंबना यह है कि आयात-निर्यात के और उदार नियम बनाने के लिए जोर दे रहे अमेरिका का रवैया खुद इस मामले में वरिधाभासी रहा है। उसने जब भी चाहा, शुल्कीय और गैर-शुल्कीय बाधा खी करने में संकोच नहीं किया। ताजा उदाहरण उसका आव्रजन विधेयक है, जिसके कानून बन जाने के बाद भारत के पेशेवरों के लिए अमेरिका में अवसर काफी सीमित हो जायेंगे। इस विधेयक की बाबत सुषमा स्वराज ने चिंता जताई, पर केरी ने कोई साफ आश्वासन नहीं दिया। केरी ने कि बौद्धिक संपदा अधिकार की वकालत की। दरअसल, भारत की दवा कंपनियों कई जीवनरक्षक दवाओं को अपेक्षया काफी कम कीमत पर मुहैया करा रही है, जिससे अमेरिका दवा उद्योग बेचैन है। दोनों पक्षों के बीच परमाणु करार का भी मसला उठा।

भारत के एटी उत्तरदायित्व कानून को अमेरिका इस करार की बाधा बता कर इसे हटवाना चाहता है। जबकि इस संबंध में खुद अमेरिका और यूरोप के कानून ज्यादा सख्त हैं। फिर, यह कानून संसद में वसित चर्चा के बाद बना है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत को प्रवेश दिलाने की अमेरिकी पेशकश के बदले इस कानून को तलियांजलि देना कगलत सौदेबाजी होगी। सुषमा स्वराज ने इस मौके का इस्तेमाल 2010 में अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की तरफ से भाजपा समेत भारत के बारे में की गई जासूसी का मसला उठाने के लिए भी किया। उन्होंने दो टूक कहा है कि ऐसी हरकत भारत को बलिबुद्ध अस्वीकार्य है। केरी जासूसी के इस खुलासे का खंडन नहीं कर सके, इस शकियत से पडि छुटने के लिए सरिफ यह कहा कि जासूसी संबंधी प्रकरण पर वे सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करना चाहते। केरी से हुई बातचीत में सुषमा स्वराज ने भारत के हितों का पक्ष मजबूती से रखा है। मोदी की संभावित यात्रा के समय भी संबंधित मसलों पर यह दृष्टि का कयम रहनी चाहिए।

फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करें - <https://www.facebook.com/Jansatta>

ट्विटर पेज पर फॉलो करने के लिए क्लिक करें- <https://twitter.com/Jansatta>